भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 672

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ शौचालयों तक पहुँच

672. श्री अमर शंकर साबलेः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के 732 मिलियन लोगों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ शौचालय उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वच्छ भारत मिशन से देश में तात्कालिक स्वच्छता मुद्दे के समाधान के लिए व्यापक जागरुकता पैदा हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में खुले में शौच से शत प्रतिशत मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वे कौन-कौन से राज्य हैं जो इस लक्ष्य को हासिल करने में पिछड़ रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) जी नहीं। दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत से अब तक 8.93 करोड़ वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो 2014 में 39% था, 12.12.2018 तक बढ़कर 97% हो गया है। भारत, वर्ष 2019 में खुले में शौच मुक्त बनने की राह पर अग्रसर है। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार स्वच्छता कवरेज **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम (जी) की शुरूआत से लेकर 12.12.2018 तक एसबीएम (जी) के अंतर्गत 8.93 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 5,35,541 गांवों, 2,43,362 ग्राम पंचायतों, 5659 ब्लॉकों, 554 जिलों और 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

(ग) से (ड.) केन्द्र सरकार ने 2 अक्तूबर, 2019 तक शत-प्रतिशत खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक, 25 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। शेष राज्य 2 अक्तूबर, 2019 तक ओडीएफ बनने की राह पर अग्रसर हैं।

अनुलग्नक-1

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 672 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 12.12.2018 की स्थिति के अनुसार शौचालय की सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालयों की सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों की प्रतिशतता
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	100.00
2	आंध्र प्रदेश	100.00
3	अरूणाचल प्रदेश	100.00
4	असम	98.83
5	बिहार	88.88
6	चण्डीगढ़	100.00
7	छत्तीसगढ़	100.00
8	दादरा और नगर हवेली	100.00
9	दमन एवं दीव समूह	100.00
10	गोवा	76.22
11	गुजरात	100.00
12	हरियाणा	100.00
13	हिमाचल प्रदेश	100.00
14	जम्मू एवं कश्मीर	100.00
15	झारखण्ड	100.00
16	कर्नाटक	100.00
17	केरल	100.00
18	लक्षद्वीप	100.00
19	मध्य प्रदेश	100.00
20	महाराष्ट्र	100.00
21	मणिपुर	100.00
22	मेघालय	100.00
23	मिजोरम	100.00
24	नागालैंड	100.00
25	ओडिशा	74.68
26	पुडुचेरी	100.00
27	पंजाब	100.00
28	राजस्थान	100.00
29	सिक्किम	100.00
30	तमिलनाडु	100.00
31	तेलंगाना	94.13
32	त्रिपुरा	95.64
33	उत्तर प्रदेश	100.00
34	उत्तराखण्ड	100.00
35	पश्चिम बंगाल	98.32
		97.21